

प्रारंभिक परीक्षा

संयुक्त योजना के साथ कौशल विकास पहलों में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी

संदर्भ

केंद्र सरकार ने अपने कौशल विकास पहलों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है, तथा उनमें से तीन को कौशल भारत कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।

3 योजनाएँ

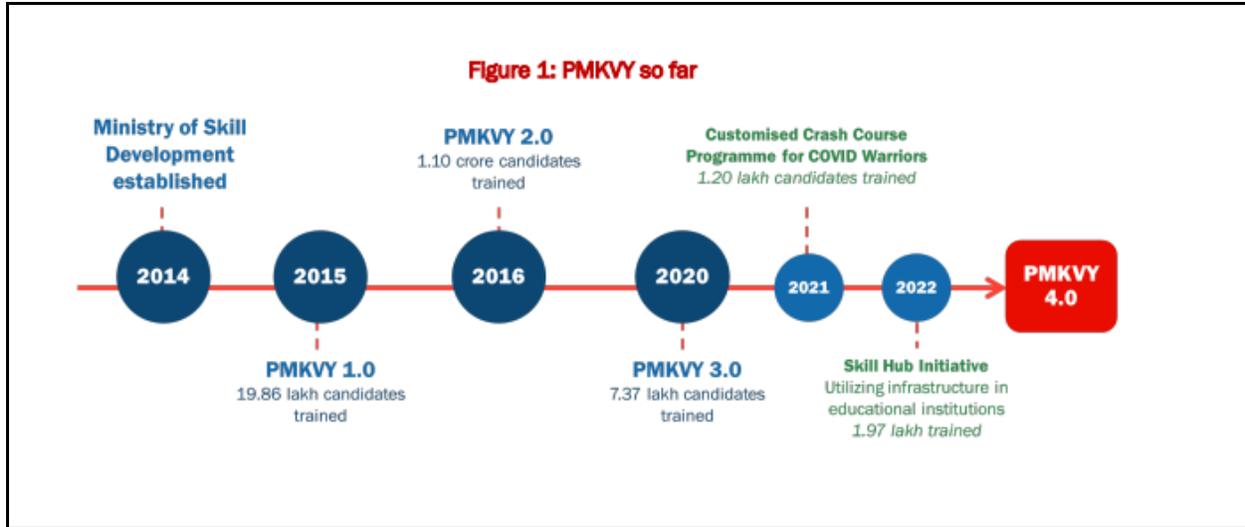
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)

- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)।
- **कार्यान्वयनकर्ता:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)।
- **अवधि:** वित्तीय वर्ष 2022-2026।
- **लक्षित लाभार्थी:** 15-59 वर्ष की आयु।
- **उद्देश्य:**
 - इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
 - व्यक्तियों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता करता है।
- **कौशल प्रमाणन:**
 - पूर्व शिक्षण अनुभव वाले व्यक्तियों को मान्यता और प्रमाणन प्रदान करता है।
 - इसमें पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) ढांचे के अंतर्गत मूल्यांकन शामिल है।

Figure 2: Broad Implementation Framework



- MSDE ने 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) लॉन्च की।



प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)

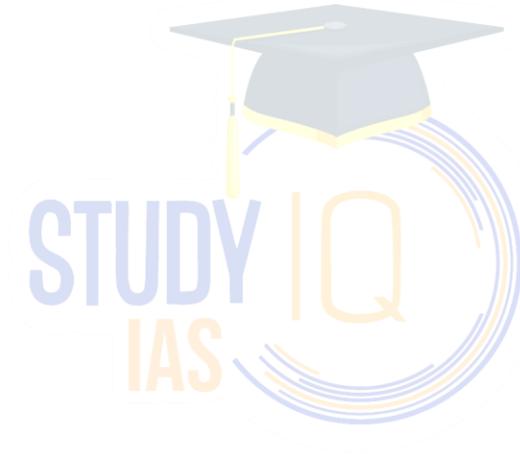
- **उद्देश्य:** प्रशिक्षता प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा से रोजगार तक सुचारू संक्रमण को सुगम बनाना।
 - वास्तविक दुनिया के कार्यस्थल अनुभव के माध्यम से उद्योग-विशिष्ट कौशल प्रदान करता है।
- **वित्तीय सहायता:** केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति प्रशिक्ष 1,500 रुपये प्रति माह तक वजीफे का 25% वहन करती है।
- **पात्रता मानदंड:** 14 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए खुला है।
- **उद्योग संरेखण:** पारंपरिक विनिर्माण के साथ-साथ AI, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा और उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षता को प्रोत्साहित करता है।
- **लघु उद्यमों के लिए समर्थन:** एमएसएमई में नामांकन को बढ़ावा देना, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तथा वंचित क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करना।

जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना

- **समुदाय-केंद्रित कौशल पहल:** किफायती, लचीला और समावेशी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **लाभार्थी:** महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (15-45 वर्ष आयु वर्ग) को लक्षित करता है।
- **सुलभ प्रशिक्षण मॉडल:** स्वरोजगार और मजदूरी आधारित आजीविका दोनों को बढ़ावा देने के लिए लचीले कार्यक्रम के साथ कम लागत वाली, घर-द्वार तक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **इसके साथ एकीकृत:** प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और उल्लस (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ)।
- **प्रमाणन और औपचारिक मान्यता:** राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित प्रमाणन।
 - रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ एकीकृत।
- **महत्व:**
 - कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर कौशल उन्नयन और पुनर्कौशलीकरण को सुदृढ़ किया जाता है।
 - कार्यबल नीतियों को आर्थिक रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) डेटा में योगदान देता है।

- कौशल प्रशिक्षण के अलावा, जेएसएस स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, लैंगिक समानता और शिक्षा पर जागरूकता के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

स्रोत: [The Hindu: Cabinet nod to rejig skilling initiatives with a combined scheme](#)



थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज (TROPEX-25)

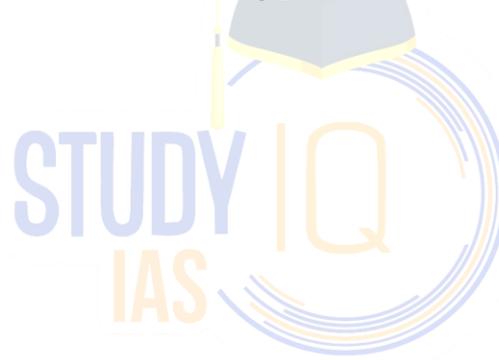
संदर्भ

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज (TROPEX-25) आयोजित कर रहा है।

TROPEX के बारे में -

- यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है।
 - युद्ध तत्परता और संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण शामिल है।
- स्थान: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में आयोजित।
- भागीदारी: भारतीय नौसेना के नेतृत्व में भारतीय सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की सक्रिय भागीदारी।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है तथा पनडुब्बी रोधी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है।
 - लाइव हथियार फायरिंग और नकली युद्ध परिदृश्य(simulated combat scenarios) शामिल हैं।
 - पारंपरिक, असममित और संकर खतरों के खिलाफ एकीकृत प्रतिक्रिया रणनीतियों का परीक्षण।
 - समन्वित संचालन के लिए संयुक्त कार्य-प्रणाली चरण और जल-थल अभ्यास शामिल हैं।

स्रोत: [The Hindu: 9 submarines, 65 ships taking part in TROPEX exercise](#)



ट्रम्प ने 'अवैध जांच' के लिए ICC पर प्रतिबंध लगाया

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल को निशाना बनाकर की गई जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिए।

समाचार में के बारे में और अधिक जानकारी

- ट्रम्प ने कहा कि अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता करने वाले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करके "अपनी शक्ति का दुरुपयोग" किया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में -

- ICC एक स्थायी न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना 1998 के रोम क़ानून के तहत 2002 में की गई थी।
 - इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।
- कार्य:** नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध के आरोपी व्यक्तियों की जांच करना, मुकदमा चलाना और फैसला सुनाना।
- सदस्य:** 123 (महत्वपूर्ण गैर-सदस्य देश: भारत, अमेरिका, चीन और रूस)
- संरचना:** न्यायालय में 18 न्यायाधीश हैं, प्रत्येक अलग-अलग सदस्य देश से, नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं।
- ICC किसी मामले की सुनवाई केवल तभी कर सकता है जब वह देश जहां अपराध किया गया हो या अपराधी का मूल देश रोम संविधि का एक पक्ष हो।
- गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद ICC गिरफ्तारी करने और संदिग्धों को ICC में स्थानांतरित करने के लिए देशों पर निर्भर करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है।

ICC और ICJ के बीच अंतर

पैरामीटर	ICC(अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय)	ICJ(अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय)
स्थापना एवं मुख्यालय	2002, हेग (नीदरलैंड)	1946, हेग (नीदरलैंड)
संयुक्त राष्ट्र संबंध	स्वतंत्र - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मामले के लिए रेफरल प्राप्त हो सकता है	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय के नाम से जाना जाता है
केस के प्रकार	व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाना	पार्टियों के बीच विवाद, और सलाहकार राय
विषय - वस्तु	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध	समुद्री विवाद, संप्रभुता, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार, संधि उल्लंघन और संधि व्याख्या, मानवाधिकार आदि।
अनुदान	रोम संविधि के पक्षकारों से प्राप्त अंशदान, संयुक्त राष्ट्र, सरकारों, निगमों, संगठनों आदि से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान।	संयुक्त राष्ट्र

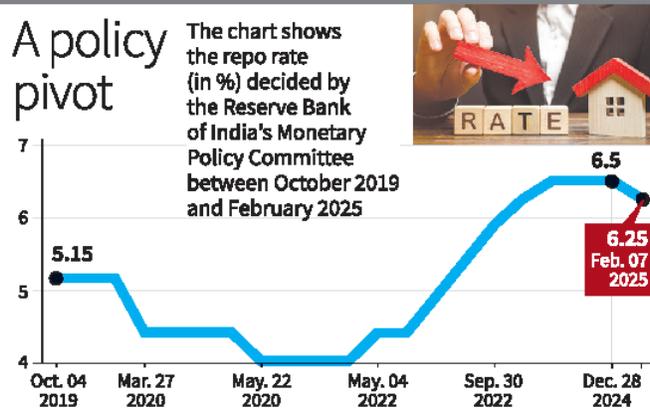
स्रोत: [The Hindu: Trump sanctions ICC for 'illegitimate probes'](#)

RBI ने विकास को गति देने के लिए ब्याज दर में 0.25% की कटौती की

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर को घटाकर 6.25% कर दिया है।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -



- इस तिमाही में मुद्रास्फीति कम होकर 4.4% और 2025-26 तक 4.2% होने की उम्मीद।
- इस वर्ष अनुमानित 6.4% से 2025-26 के लिए 6.7% की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगाया गया।
- विदेशी मुद्रा भंडार 630.6 बिलियन डॉलर रहा, जो 10 महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करता है।

मौद्रिक नीति समिति

- एमपीसी का गठन 2016 में आरबीआई अधिनियम के तहत भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था (उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर)

- संरचना (अध्यक्ष + 5 सदस्य): कोरम: 4 सदस्य।
 - आरबीआई गवर्नर - पदेन अध्यक्ष
 - आरबीआई के डिप्टी गवर्नर + आरबीआई से एक और सदस्य, जिसे केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नामित किया जाएगा।
 - तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।



- एमपीसी के सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
- एमपीसी को वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी आवश्यक है।
- एमपीसी बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है (जो उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं। बराबर मत मिलने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।
- समिति का निर्णय आरबीआई के लिए बाध्यकारी है।

MPC द्वारा रेपो दर का उपयोग कैसे किया जाता है?

- **मुद्रास्फीति नियंत्रण:** MPC मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए रेपो दर को समायोजित करती है।

- उच्च रेपो दर से बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
- इसके विपरीत, कम रेपो दर से उधार देने में वृद्धि होती है और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है।
- **तरलता प्रबंधन:** रेपो दर में परिवर्तन करके, MPC वित्तीय प्रणाली में तरलता को प्रभावित करती है।
 - उंची दर से तरलता कठिन हो जाती है, जबकि कम दर से तरलता की स्थिति आसान हो जाती है।
- **आर्थिक विकास:** रेपो दर अर्थव्यवस्था में समग्र ब्याज दरों को प्रभावित करती है।
 - रेपो दर कम करने से उधार और निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
 - इसे बढ़ाने से अति ताप या मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने के लिए विकास को धीमा किया जा सकता है।
- **विनिमय दर स्थिरता:** रेपो दर में परिवर्तन पूंजी प्रवाह और निवेशक भावना को प्रभावित करके रुपये के मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

RBI इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है

- **रेपो दर:** यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में ऋण देता है।
- **स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ):** यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग RBI वाणिज्यिक बैंकों से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए करता है।
- **तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ):** यह RBI द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जरूरत पड़ने पर तरलता प्राप्त करने या सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले RBI के पास एक रात के आधार पर अतिरिक्त धनराशि जमा करने के लिए प्रदान की गई सुविधा है।
- **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर):** बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में RBI के पास जो धनराशि रखनी चाहिए, वह नकद आरक्षित अनुपात है। उच्च सीआरआर बैंकों के लिए उधार देने हेतु उपलब्ध धनराशि को कम कर देता है, जिससे बाजार में तरलता कम हो जाती है।
 - **वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर):** बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना चाहिए। उच्च एसएलआर से बैंकों के पास उधार देने के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह सीमित हो जाता है।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: यदि RBI विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का फैसला करता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

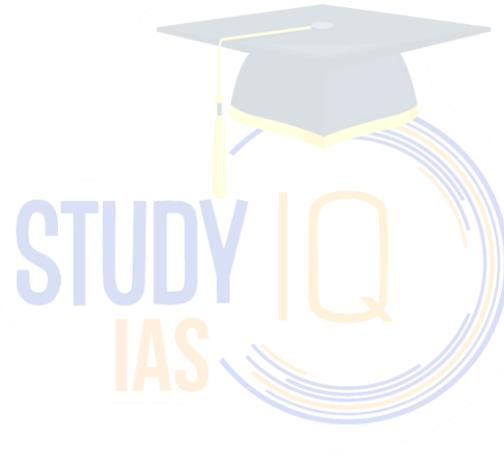
1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुविधा दर में वृद्धि
3. बैंक दर और रेपो दर में कटौती

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर:(b)

स्रोत: [The Hindu: RBI slashes rate by 0.25% to revive growth](#)



समाचार में स्थान

जॉर्जिया अमेरिका की तर्ज पर नया विदेशी प्रभाव कानून अपनाएगा

जॉर्जिया

→ **समाचार?** जॉर्जिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने घोषणा की कि वह विवादास्पद "विदेशी प्रभाव" कानून को अमेरिकी कानून के समान संस्करण से बदल देगी।



- **स्थान:** काकेशस क्षेत्र, काला सागर के पूर्वी किनारे पर।
 - **राजधानी:** त्बिलिसी
 - **सीमावर्ती क्षेत्र:** रूस, आर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान और काला सागर।
 - **1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा था।**
- स्रोत: [The Hindu: Georgia to adopt new foreign influence law modelled after U.S.](#)

संपादकीय सारांश

वैश्विक AI चर्चाओं में भारत की आवाज़ गूंजनी चाहिए

संदर्भ

सियोल स्टेटमेंट ऑफ इंटरेंट के बाद नवंबर 2024 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में AI सुरक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत देशों ने AI सुरक्षा पर सहयोग करने का संकल्प लिया।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी

- इस नेटवर्क का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं और सामंजस्यपूर्ण सुरक्षा मानकों को स्थापित करने के लिए AI सुरक्षा अनुसंधान, तकनीकी विशेषज्ञता और नीति नवाचार में वैश्विक प्रयासों को एकीकृत करना है।
- हालाँकि, AI को अपनाने वाला एक प्रमुख देश होने के बावजूद भारत अभी तक इस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल नहीं हुआ है।

AI की विकासशील प्रकृति

- AI एक सीमाहीन तकनीक है, जो स्वास्थ्य सेवा, वित्त, कृषि और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है।
- भारत में 30% AI अपनाने (वैश्विक औसत 26% से अधिक) और 10% चैटजीपीटी उपयोगकर्ता भारतीय होने के साथ, AI भारत की अर्थव्यवस्था में गहराई से एकीकृत हो गया है।
- हालाँकि, भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, अमेरिका द्वारा चीन की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए उन्नत AI पर निर्यात नियंत्रण लगाया जा रहा है।
- यह महत्वपूर्ण AI प्रौद्योगिकियों तक भारत की पहुंच को प्रभावित कर सकता है, जिससे AI शासन में वैश्विक भागीदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

भारत का रुख

- भारत अपने बढ़ते AI पारिस्थितिकी तंत्र के बावजूद अभी तक AI सुरक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल नहीं हुआ है।
- इस मंच से अनुपस्थिति से भारत के वैश्विक AI नियमों पर प्रभाव खोने का खतरा है।
- अंतर्राष्ट्रीय AI सुरक्षा पहलों में शामिल होना निम्नलिखित के लिए आवश्यक है:
 - भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना - नैतिक, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी AI विकास सुनिश्चित करना।
 - भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना - AI शासन ढांचे को आकार देना और वैश्विक मानकों को प्रभावित करना।
 - भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान - AI प्रौद्योगिकी तक पहुंच पर संभावित प्रतिबंधों को रोकना।
 - नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना - AI वित्तपोषण और साझेदारी को आकर्षित करने के लिए नीतियों को वैश्विक मानदंडों के साथ संरेखित करना।
- भारत की ताकत, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और मजबूत तकनीकी प्रतिभा पूल, उसे निष्क्रिय पर्यवेक्षक बने रहने के बजाय वैश्विक AI सुरक्षा चर्चाओं का नेतृत्व करने की स्थिति में रखते हैं।
- राष्ट्रीय AI सुरक्षा संस्थान और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता की तत्काल आवश्यकता है।

AI की दौड़ में भारत को क्या करना चाहिए?

- **लागत प्रभावी AI समाधान विकसित करना:** भारत को इसरो के दृष्टिकोण के समान, कम ऊर्जा, लागत प्रभावी AI मॉडल पर ध्यान केंद्रित करके दक्षता के साथ नवाचार करना चाहिए, जो तेजी से बढ़ सकता है।
 - इससे भारत कम संसाधनों में अधिक कार्य कर सकेगा तथा यह सुनिश्चित होगा कि AI सुलभ और टिकाऊ हो।
- **ओपन-सोर्स AI इकोसिस्टम को मजबूत करना:** ओपन-सोर्स AI मॉडल को प्रोत्साहित करने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और AI विकास का लोकतंत्रीकरण होगा।
 - भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं (जैसे, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा) को पूरा करने वाले डोमेन-विशिष्ट AI समाधान बनाने में स्टार्टअप्स और डेवलपर्स का समर्थन करना।
- **भारतीय डेटा के साथ संप्रभु AI मॉडल बनाना:** भारतीय डेटासेट पर प्रशिक्षित अग्रणी AI मॉडल विकसित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हैं और विदेशी पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं।
 - अनुप्रयोग-स्तर AI से आगे बढ़ें और आधारभूत मॉडल और बुनियादी ढांचे सहित एक संपूर्ण AI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करें।
- **AI हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर स्वतंत्रता में निवेश करना:** GPU, AI के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध भारत की उन्नत चिप्स तक पहुंच को सीमित करते हैं।
 - भारत को चिप निर्माण, AI कंप्यूटिंग शक्ति और ऊर्जा-कुशल हार्डवेयर में निवेश के माध्यम से घरेलू अर्धचालक क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए।
- **बहुभाषी और बहुविध AI मॉडल विकसित करना:** भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ हैं - AI को वास्तव में समावेशी बनाने के लिए AI मॉडल को बहुभाषी और बहुविध क्षमताओं का समर्थन करना चाहिए।
 - भाषिनी जैसी पहलों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
- **वैश्विक AI आपूर्ति श्रृंखलाओं में टियर-1 स्थिति सुरक्षित करना:** एक क्राड भागीदार के रूप में, भारत को उच्च-स्तरीय GPU और AI प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंधों से बचने के लिए AI प्रसार नीतियों में टियर-1 स्थिति की मांग करनी चाहिए।
 - AI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक अप्रतिबंधित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक और व्यापार वार्ता को मजबूत करना।
- **मिशन-संचालित, तत्काल दृष्टिकोण अपनाना:** AI एक वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकता है - भारत को यूपीआई, आधार और डिजिटल बुनियादी ढांचे में अपनी सफलता के समान तत्परता और मिशन-मोड निष्पादन के साथ कार्य करना चाहिए।
 - नीति, वित्त पोषण और AI अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इंडियाAI मिशन टास्क फोर्स की स्थापना करना।

स्रोत: [The Hindu: India's voice must resonate in global AI conversations](#)

[Indian Express: AI Race: What India Should Do?](#)

प्रौद्योगिकी और समतापूर्ण शिक्षा की चुनौती

संदर्भ

प्रौद्योगिकी ने शिक्षा में क्रांति ला दी है, लेकिन वंचित वर्ग के लिए इसकी पूरी क्षमता का अभी भी उपयोग नहीं हो पाया है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी ने कैसे मदद की

- **शिक्षण सामग्री तक पहुंच में वृद्धि:** कोविड-19 महामारी के दौरान स्मार्टफोन शिक्षा के लिए एक प्राथमिक उपकरण बन गया, जिससे पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों के विकल्प के रूप में पाठ्य सामग्री, कार्यपत्रकों और वीडियो तक पहुंच आसान हो गई।
 - शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आम हो गये।
- **ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच:** 2018 में, 36% ग्रामीण परिवारों के पास स्मार्टफोन थे, जो 2024 (ASER 2024) तक बढ़कर 84% हो गए।
 - अब अधिक संख्या में बच्चों के पास निजी स्मार्टफोन हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा तक उनकी व्यक्तिगत पहुंच बढ़ रही है।
- **भाषा संबंधी बाधाओं पर काबू पाना:** AI-संचालित उपकरण अब स्थानीय भाषाओं में श्रुतलेख, लेखन और अनुवाद की अनुमति देते हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा अधिक समावेशी हो जाती है।
- **समुदाय-आधारित शिक्षा की संभावना:** महामारी के दौरान महाराष्ट्र में संचालित प्रसारण शिक्षण कार्यक्रमों से पता चला कि समूह शिक्षण मॉडल दूरदराज के गांवों में भी प्रभावी हो सकते हैं।
- **माताओं की शिक्षा के लिए समर्थन:** बड़ी संख्या में माताओं (40%) की स्कूली शिक्षा बहुत कम है, लेकिन डिजिटल शिक्षा उनकी शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता कर सकती हैं।

समतामूलक शिक्षा की चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन:** यद्यपि स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ी है, फिर भी इंटरनेट की पहुंच और सामर्थ्य अभी भी बाधाएं बनी हुई हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों में।
 - डिवाइस साझा करने से व्यक्तिगत शिक्षण के अवसर सीमित हो जाते हैं।
- **गुणवत्ता बनाम पहुंच:** नामांकन दर में वृद्धि हुई है, लेकिन सीखने के परिणाम खराब बने हुए हैं (एएसईआर रिपोर्ट)।
 - केवल स्कूलों या डिजिटल उपकरणों तक पहुंच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी नहीं है।
- **भाषा और विषय-वस्तु का अंतराल:** यद्यपि AI-संचालित अनुवाद में सुधार हुआ है, फिर भी कई शैक्षिक संसाधन अभी भी अंग्रेजी या शहर-केंद्रित भाषाओं में हैं, जिससे वे ग्रामीण शिक्षार्थियों के लिए कम उपयोगी हैं।
- **शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** कई शिक्षकों में कक्षा में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए डिजिटल कौशल का अभाव है।
 - पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ अभी भी प्रभावी बनी हुई हैं, जिससे डिजिटल शिक्षण का प्रभाव सीमित हो रहा है।
- **शिक्षा में लैंगिक अंतर:** माताओं और लड़कियों के बीच स्मार्टफोन का कम स्वामित्व ऑनलाइन सीखने के अवसरों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
 - सामाजिक मानदंड और कम उम्र में विवाह महिला शिक्षा को और बाधित करते हैं।
- **आर्थिक बाधाएँ:** निजी स्कूल और सशुल्क डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित छात्रों के बीच की खाई को चौड़ा करते हैं।

- निम्न आय वाले परिवारों के लिए किफायती डिजिटल शिक्षा समाधान का अभाव।
- **मानकीकरण बनाम स्थानीय आवश्यकताएं:** राष्ट्रीय या वैश्विक पाठ्यक्रम अक्सर क्षेत्रीय और स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं की अनदेखी करते हैं।
 - AI-संचालित शिक्षा को सांस्कृतिक और प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए।
- **लाभ-संचालित तकनीकी नवाचार:** अधिकांश एड-टेक समाधान लाभ-संचालित होते हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए पहुंच को सीमित कर देते हैं।
 - सार्वजनिक डिजिटल शिक्षा में परोपकारी निवेश इस अंतर को पाटने के लिए अपर्याप्त है।

आगे की राह

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- सांस्कृतिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री का स्थानीयकरण करना।
- शिक्षकों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- निःशुल्क एवं ओपन-सोर्स शैक्षिक प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।
- लक्षित नीतियों और डिजिटल पहुंच कार्यक्रमों के साथ महिला शिक्षा का समर्थन करना।

निष्कर्ष

अमेरिका या चीन का तकनीकी उपनिवेश बनने से बचने के लिए, भारत को तेजी से आत्मनिर्भर AI क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए। हार्डवेयर स्वतंत्रता, ओपन-सोर्स AI, संप्रभु मॉडल और नीति प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करके, भारत वैश्विक AI नेता के रूप में अपनी जगह सुरक्षित कर सकता है। AI क्रांति अभी हो रही है, और भारत को इसका नेतृत्व करना चाहिए, न कि उसका अनुसरण करना चाहिए।

स्रोत: [The Hindu: Technology and the challenge of equitable education](#)



विस्तृत कवरेज

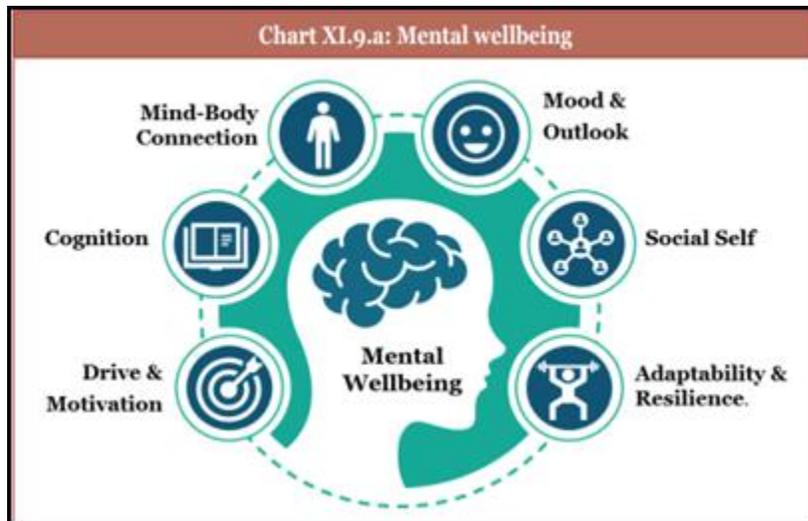
भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा का विकास

संदर्भ

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मानसिक कल्याण में हमारी सभी मानसिक-भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताएं शामिल हैं।

मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से निपटने, अपनी क्षमता को पहचानने, प्रभावी ढंग से सीखने, उत्पादक रूप से काम करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाती है।



उद्धरण

- “बिना जांचे-परखे जीवन जीने लायक नहीं है।” – सुकरात

कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य के रुझान

- **वैश्विक रुझान:** युवा पेशेवरों में आत्महत्याओं में चिंताजनक वृद्धि सामने आई है, जिसका प्राथमिक कारण कार्यस्थल पर अत्यधिक तनाव बताया गया है।
- **जापान में संकट:** 'कारोशी' (अत्यधिक काम से मृत्यु) शब्द का प्रयोग जापान में किया जाता है, जहां 2023 में 2,900 लोगों ने अत्यधिक काम के कारण आत्महत्या कर ली।
- **भारत में आंकड़े:** स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में निजी क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों में 11,486 आत्महत्याएं दर्ज की गईं।
 - **हाल की घटनाएं:** जुलाई में, एक बहुराष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्म की 26 वर्षीय महिला अधिकारी ने अत्यधिक कार्य दबाव के कारण अपनी जान ले ली।

- सितम्बर में, चेन्नई में 15 वर्षों के अनुभव वाले 38 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कार्य तनाव से उत्पन्न अवसाद के उपचार के दौरान अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
- ये घटनाएँ बाहरी सफलता और आंतरिक मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों, जैसे अवसाद और चिंता, के बीच संघर्ष को उजागर करती हैं।

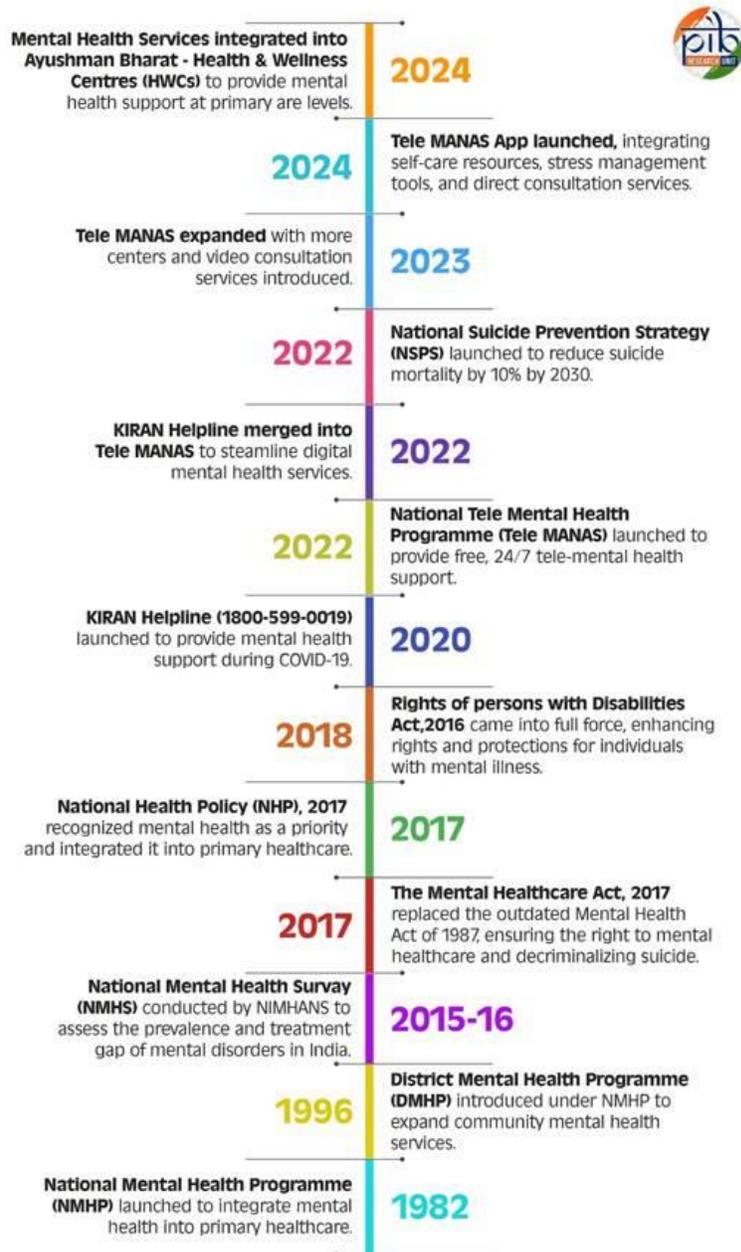
बढ़ते तनाव और चिंता के कारण

- कार्यकुशलता और भौतिक संपदा पर आधुनिक जोर आत्म-जागरूकता से वियोग पैदा करता है और मानसिक स्वास्थ्य संकट में योगदान देता है।
- **शहरी दबाव:** शहरी जीवन का दबाव, वित्तीय अस्थिरता और गलाकाट प्रतिस्पर्धा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
 - कई व्यक्तियों का मानना है कि भौतिक सफलता सच्ची खुशहाली के बराबर नहीं है, जिससे उनमें अलगाव और उद्देश्यहीनता की भावना पैदा होती है।
 - लाभ, दक्षता और लागत में कटौती पर ध्यान केंद्रित करने से कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप काम के घंटे लंबे हो जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है।
- **उपभोक्तावाद:** उपभोक्तावाद पर बढ़ता ध्यान एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां स्थिति को विलासिता की वस्तुओं द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तनाव और सामाजिक तुलना होती है।
 - भौतिक सम्पदा के पीछे भागने का यह चक्र भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है।

भारत में खराब मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण

- **जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव:** भारत में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को अक्सर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी चिंता के रूप में नहीं माना जाता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी:** भारत में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है।
 - **उदाहरण:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-2016) ने बताया कि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं।
- **उपचार अंतराल:** जागरूकता की कमी, कलंक और पेशेवरों की कमी के कारण मानसिक विकार वाले 70% से 92% व्यक्तियों को उपचार नहीं मिल पाता है।
- **कम बजट आवंटन:** जबकि विकसित देश अपने स्वास्थ्य देखभाल बजट का 5-18% मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित करते हैं, भारत केवल 1.11% आवंटित करता है।

सरकारी पहल



आगे की राह

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सुझाव दिया गया है:
 - स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना: छात्रों में चिंता, तनाव और व्यवहार संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप रणनीतियाँ।
 - कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य नीतियों में सुधार: नौकरी के तनाव, लंबे कार्य घंटों और थकान की समस्या का समाधान करना।
 - डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: टेली मानस को मजबूत करें और AI-आधारित मानसिक स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करना।

- **ब्राज़ील की पहल:** ब्राज़ील में सामुदायिक उद्यानों ने निवासियों के बीच सामाजिक संबंधों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। भारत में भी इसी तरह की पहल शहरी जीवन के कारण होने वाले अलगाव को कम करने में मदद कर सकती है।
- **खुली बातचीत को बढ़ावा देना:** मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली चर्चा को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति का निर्माण करने से कलंक को खत्म करने में मदद मिल सकती है।

स्रोत: **PIB: Advancing Mental Healthcare in India**

